पुतिन-जिनपिंग के नए मंसूबे

कुछ पश्चिमी देशों ने यह अयथार्थवादी आस भी प्रकट की थी कि उनकी 'यूक्रेन योजना' में चीन भी मदद करेगा और रूस को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए मना लेगा। लेकिन यह उम्मीदें अब बिखर चुकी हैं। रूस-चीन संयुक्त घोषणापत्र में बाकायदा कहा गया है कि अमेरिका और इसके सहयोगियों को सभी मुल्कों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं की कद्र करनी होगी, साथ ही जोड़ा कि संघर्ष से बचा जाना चाहिए। रूस और चीन ने जोर देते हुए कहा कि एक समस्याओं का स्थिर निदान निकालने के लिए 'जिम्मेवाराना संवाद' सबसे बेहतर तरीका है।

जी. पार्थसारथी

लेखक पूर्व डॉरिश राजनयिक हैं।

अमेरिका और इसके पश्चिमी सहयोगी मुल्कों को आस और विश्वास है कि पुतिन-जिनपिंग शिखर वार्ता से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। मास्को शिखर वार्ता में रूस और चीन ने दोनों देशों को अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था से दरपेश चुनौतियों से निपटने के लिए बृहद योजना पर विमर्श किया। अमेरिका और उसके यूरोपियन सहयोगी यूक्रेन पर रूसी चढ़ाई के बाद से उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग बार-बार कर रहे हैं।

कुछ पश्चिमी देशों ने यह अयथार्थवादी आस भी प्रकट की थी कि उनकी 'यूक्रेन योजना' में चीन भी मदद करेगा और रूस को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए मना लेगा। लेकिन यह उम्मीदें अब बिखर चुकी हैं। रूस-चीन संयुक्त घोषणापत्र में बाकायदा कहा गया है कि अमेरिका और इसके सहयोगियों को सभी मुल्कों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं की कद्र करनी होगी, साथ ही जोड़ा कि संघर्ष से बचा जाना चाहिए। रूस और चीन ने जोर देते हुए कहा कि एक समस्याओं का स्थिर निदान निकालने के लिए 'जिम्मेवाराना संवाद' सबसे बेहतर तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रासंगिक रचनात्मक प्रयासों की सहायता करनी चाहिए।

वास्तव में यह घोषणा सभी पक्षों से ऐसे काम बंद करने का आह्वान करती है जिनसे तनाव बढ़ता हो, ताकि किसी संकट को और गहराने या हाथ से बाहर निकलने से बचाया जा सके। घोषणापत्र का निष्कर्ष है कि चीन और रूस तमाम एकतरफा प्रतिबंध, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी नहीं मिली, उनका पुरजोर विरोध करते हैं। अमेरिका ने खोजी पत्रकार सैमूर हर्ष द्वारा लगाए इन इल्जामों को खारिज किया है कि रूस से जर्मनी को गैस ले जाने वाली और समुद्र सतह पर बिछी 'बेक्सी' गैस-पाइपलाइन को (जिसे नॉर्थस्ट्रीम भी कहा जाता है) विस्फोट से उड़ाने के पीछे उसका हाथ है।

रूस और चीन ने दोटूक कहा 'भू-राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल के लिए अतिवाद का झंडा बुलंद करवाना और आतंकी एवं अतिवादी गुटों का इस्तेमाल करना बंद हो।' साथ ही यह मांग भी की है 'बेक्सी पाइपलाइन विस्फोट की जांच के लिए एक ईमानदार, निष्पक्ष और व्यावसायिक जांच हो।' यह बात अमेरिका और जर्मनी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की इज्जत करने में उच्च मूल्यों का पालन करने वाले जर्मनी के लिए- अगर वे यह दावा करते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को धता बताकर किसने जर्मनी के लिए बहुत महत्व रखने वाली गैस-पाइपलाइन को उड़ाया है। सबसे अहम, रूस और चीन का यह कहना कि 'सभी मुल्कों की वैध सुरक्षा चिंताओं की कद्र होनी चाहिए, और आग में घी डालकर दो पक्षों में तनातनी नहीं बढ़ानी चाहिए', इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इन आकांक्षाओं और उम्मीदों पर पानी फिरा है कि चीन रूस को यूक्रेन पर लचीलापन अपनाने के लिए मना लेगा।

यूक्रेन के मामले में चीन ने रूसी रवैये को यह कहकर तगड़ा समर्थन दिया है कि समस्याएं सुलझाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता जिम्मेवाराना संवाद है। सबसे महत्वपूर्ण, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस का साथ देने का भरोसा दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 'संघर्ष को हवा देने वाले पक्ष तमाम वह काम बंद हों जिनसे तनाव बढ़ता है और युद्ध लंबा न खिंच पाए।' पुतिन अपने चीनी मेहमान से इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं रख सकते थे। अब देखना यह है कि क्या चीन को वह सैन्य साजो-सामान देगा, जिसकी उसे जरूरत है। इस घटनाक्रम से जिन देशों को सबसे अधिक चिंता होगी वे हैं, अमेरिका और इसके नाटो सहयोगी। रूस यूक्रेन पर अपनी कार्रवाई पर अब चीन की मदद लेकर निश्चिंत है।

चीन और रूस ने यह संकेत भी दिया है कि उन्हें पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों की जरा परवाह नहीं। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका को इस हकीकत के मद्देनजर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि रूस उस क्रीमिया में अपने सामरिक हित बरकरार रखना चाहता है, जो तीन सदियों से ज्यादा उसके नियंत्रण में रहा था और साथ ही पूरबी यूक्रेन में बसे रूसी भाषी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को दृढ़संकल्प है। पुतिन-जिनपिंग घोषणापत्र में इन दोनों की ओर स्पष्ट है कि वे एक-दूसरे के सुरक्षा हितों को बचाये रखने में साथ खड़े होने को तत्पर हैं। हालांकि घोषणापत्र में कुछ विषयों पर भारत का भी जिक्र आया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिस पर भारत को आपत्ति हो। अब यह उभरकर आया है कि अमेरिका और इसके नाटो सहयोगियों से निपटना रूस-चीन का साझा हित है। गौरतलब है कि चीन भारत का सकारात्मक रूप से जिक्र करने से बचा है। चीन के लगातार बढ़ते घमंड की जरा भी जानकारी रखने वाले किसी शख्स को हैरानी नहीं होगी कि वह अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बूते दुनिया में अपनी मान्यता बतौर एक वैश्विक शक्ति होने की हसरत रखता है।

इसके अलावा, चीन का काफी ध्यान तेल संपन्न खाड़ी क्षेत्र में रूस के साथ मिलकर संयुक्त सुरक्षा तंत्र बनाने की तरफ है। चीन और रूस इसको लेकर भी काफी खुश हैं कि बाइडेन प्रशासन की अनाड़ी कूटनीति के चलते वे ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती प्रक्रिया बनवाने में सफल रहे हैं। इसी किस्म का सामान्य दोस्ताना रिश्ता वे सीरिया और सऊदी अरब के बीच बनवाने के भी इच्छुक हैं। इस घटनाक्रम के नतीजे ने खाड़ी क्षेत्र में तगड़ी रूस-चीन उपस्थिति बना दी है और अब वे इस तेल संपन्न इलाके में संयुक्त सुरक्षा तंत्र बनाने को दृढ़निश्चयी हैं।

रूस-चीन की युगलबंदी का प्रभाव रूस-भारत रिश्तों पर पड़ने को लेकर कई मर्तबा चिंताएं भी जताई जाती हैं। भारत अपनी सेना का निरंतर आधुनिकीकरण करने में सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता आया है। भारत के स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी निर्माण में भी रूस काफी मददगार रहा है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलें भी बना रहे हैं, जिन्हें मित्र देशों को बेचा जा रहा है, जिसके खरीदार और बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा भारत को रूस वाजिब दामों पर पेट्रोलियम पदार्थ मुहैया करवा रहा है जो भारत के विदेशी मुद्रा भुगतान में संतुलन बनाने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर रूस जानता है कि भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग बढ़ रहे हैं और यह भी कि हिंद-प्रशांत महासागरीय इलाके में सुरक्षा स्थायित्व के लिए क्वाड और आई2यू2 गुटों की सदस्यता एवं अन्य मंचों पर भारतीय भागीदारी आगे भी बढ़ेगी। यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी मदद के चलते रूस उससे खफा है। लेकिन चीन की हरचंद कोशिश होगी कि वह पाकिस्तान की मदद करने को रूस को मनाए। इस सबके बीच, अपनी सामरिक सार्वभौमिकता रखना भारत की सुरक्षा एवं विदेश नीति की पहचान बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए।